

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata – 700 001

Serial Circular No. 125/2017

No. E/PC-VII/2016/Policy

Kolkata, Dated: 18/09/2017

All Concerned

(as per standard list)

**Sub: Payment on account of discontinued allowances – Daily
Officiating Allowance.**

Following instructions of Ministry of Railways (Railway Board) issued vide their letter No. **E(P&A)I-2011/FE-4/1 dated 05/09/2017** (PC-VII No.56, **RBE No.120/2017**) on the above subject, are communicated herewith along with Hindi version, for information and necessary action. DA: Hindi Version.

DA: Hindi version.


(U. Lahiri)
Dy. Chief Personnel Officer/R
For Chief Personnel Officer
Phone no.: 24103

*Copy of Board's letter No. **E(P&A)I-2011/FE-4/1 dated 05/09/2017** (PC-VII No.56, **RBE No.120/2017**) addressed to the GMs/All Indian Railways & PUs.*

Sub: Payment on account of discontinued allowances – Daily Officiating Allowance.

Consequent upon the decision taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the President is pleased to decide that disbursement of all existing allowances which have not been specifically recommended for continuation in terms of the Ministry of Finance's Resolution dated 6th July, 2017 shall be discontinued from 1st July, 2017. Since, the Daily Officiating Allowance has not been specifically recommended for continuation in the said Resolution dated 6th July, 2017, it ceases to exist with effect from 1st July, 2017.

2. It shall be the responsibility of the Heads of the Department to ensure that no bill relating to disbursement in respect of Daily Officiating Allowance is drawn by the Head of office/Drawing & Disbursing Officers under their purview/jurisdiction. Pay and Accounts officers shall ensure that no payment is effected if any such bill relating to the disbursement of the discontinued allowance is submitted to them. If such bills are received, they should be returned to the DDO and intimation thereof shall also be given to the Head of the Department and Chief Controller of Accounts.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Sd/-(Anil Kumar)
Dy. Director/E(P&A)-I

Index No.1057: All existing allowances which have not been specifically recommended for continuation as per Ministry of Finance's Resolution dated 06/07/2017, including Daily Officiating Allowance, will be discontinued from 01/07/2017.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 56

आरबीई सं. 120/2017

सं. ई(पी एंड ए)-2011/एफई-4/1

नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2017

महाप्रबंधक और प्रधान वित्तीय सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: समाप्त कर दिये गए भत्तों का भुगतान - दैनिक स्थानापन्न भत्ता।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति सहर्ष निर्णय करते हैं कि सभी उन मौजूदा भत्तों, जिन्हें वित्त मंत्रालय के दिनांक 6 जुलाई, 2017 के संकल्प के अनुसार जारी रखने के लिए विशिष्ट रूप से सिफारिश नहीं की गई है, को 1 जुलाई, 2017 से समाप्त कर दिया गया जाएगा। चूंकि 6 जुलाई, 2017 के उक्त संकल्प में दैनिक स्थानापन्न भत्ते को जारी रखने के लिए विशिष्ट रूप से सिफारिश नहीं की गई है इसलिए यह भत्ता 1 जुलाई, 2017 से समाप्त कर दिया गया है।

2. विभाग के अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनकी सीमा/अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यालय के प्रधान/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा दैनिक स्थानापन्न भत्ते के संवितरण से संबंधित किसी बिल को आहरित नहीं किया जाता है। वेतन एवं लेखा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि समाप्त कर दिये गए भत्ते के संवितरण से संबंधित कोई ऐसा बिल उनको प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे बिल प्राप्त होते हैं तो उन्हें डीडीओ को वापस लौटा दिया जाना चाहिए और इस बारे में विभाग के अध्यक्ष तथा मुख्य लेखा नियंत्रक को भी सूचित किया जाएगा।

3. इसे रेलवे मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)

उप निदेशक/ई(पी एंड ए)-I

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)-2011/एफई-4/1

नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अयोधित।

मु.आ.ई.जी, मु.परि.अध्यक्ष, मु.स.अधि, प्र.मु.ई.जी.
CME, COM, CEO, PCE
मु.आ.ई.जी, मु.पि एवं मु.स.ई.जी, मु.स.अधि, मु.आ.अध्यक्ष
CEE, CSTE, CAO / C, CCM

OSR

वि

कृते वित्त आयुक्त/रेलें